रणजीत टाइम्स

इंदौर

गुरुवार, 11 सितम्बर, 2025

वर्ष 01 | अंक 227 | कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

पीएम टेक्सटाईल पार्क का प्रधानमंत्री करेंगे भूमिपूजन

17 सितम्बर को बदनावर के भैंसोला में देश के पहले टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखेंगे। यह पार्क मालवा और निमाड़ की साझी बुनियाद पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है। इस पार्क में जो वस्त्र परिधान बनेंगे वो मालवा की अधोसंरचना और निमाड़ के कॉटन व श्रम के साझे सहयोग से निर्मित होंगे। यह पार्क किसानों के साथ ही युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनाएगी। प्रदेश के रोजगार क्षेत्र में इस तरह यह एक अनोखा उद्योग होगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से दो लाख रोजगार सर्जित होंगे। इस पार्क की खासियत यह भी है कि यहाँ फार्म से फाइबर और फैशन से फैक्टरी फिर फॉरेन की अवधारणा को पूरा करने की शुरुआत शासन द्वारा लगभग 2 वर्ष से प्रारम्भ की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जुलाई में दुबई व स्पेन

फिर अगस्त में लुधियाना और अब कोलकाता में निवेशकों को साथ संपर्क कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी अहम कड़ी साबित होगी। पीएम मित्रा पार्क के 150 किमी के दायरे में सड़क, रेल और वायु सेवा की कनेक्टिविटी पीएम मित्रा पार्क की बदनावर से देश व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से बेहतर कनेक्टिविटी में है। बदनावर भैंसोला सड़क, रेल और वायु मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। यहां से मुम्बई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल के लिए मेघनगर व रतलाम रेलवे यार्ड 100 किमी. के दायरे में है। इसके अलावा इंदौर एयरपोर्ट से 120 किमी. और अहमदाबार 330 किमी. दूरी पर है। साथ ही यहां से 70 किमी. दूर एक अन्य एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है। एक्सप्रेस-वे से जहाँ देश की राजधानी के अलावा राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों से कनेक्टिविटी सुगम होगी। वहीं इस क्षेत्र की चारों दिशाओं से और बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बदनावर से थांदला रोड एनएचएआई द्वारा मंजूर कर लिया गया है।

भैंसोला में आकार ले रहे टेक्सटाइल पार्क के सबसे सकारात्मक पहलुओं में निमाड़ के किसान और यहां की कपास वाली उपजाऊ भूमि भी है। यहां के किसानों को अब वस्त्र निर्माण की पूर्ति के लिए कपास उत्पादन के बेहतर अवसर होंगे। जो अब से पहले कभी नही मिले है। कृषि विभाग से मिली जानकारी अनुसार इंदौर संभाग के बड़वानी, खरगोन, खंडवा बुरहानपुर और धार के किसानों द्वारा 5 लाख हेक्टेयर से अधिक रकबे में कपास की खेती की जाती है। पीएम मित्रा योजना के तहत निर्मित हो रहे इस पार्क का उद्देश्य भी यहीं है कि पूरे देश में एकीकृत टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक ही स्थान पर विकसित करना है। यानी निमाड़ के खेतों में उपजे जाने वाले कपास को बदनावर के इस पार्क में फाइबर का रूप दिया जाए। यह योजना पाँच एफ पर आधारित है, इसमें फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन तक की अवधारणा को पूरा किया जाएगा। जहाँ फार्म यानी निमाड़ के खेतों का कपास और बदनावर में तैयार हो रहा पार्क जहाँ फाइबर से फैशन तैयार होगा।

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित की दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों से दूध क्रय दरों में दोबारा की गई सर्वाधिक वृद्धि

दुग्ध उत्पादकों ने दूध क्रय दर वृद्धि पर खुशियां व्यक्त करते हुए कहा कि यह इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के इतिहास में सर्वाधिक दूध क्रय दर है । एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (एमपीसीडीएफ) भोपाल से संबद्ध इंदौर सहकारी दुग्ध संघ अंतर्गत दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों से क्रय किए जाने वाले दूध क्रय दर में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। दुग्ध उत्पादकों से रूपए 840 प्रति किग्रा फैट से दूध क्रय करने का निर्णय लिया गया है, जो 11 सितंबर 2025 से प्रभावशील होगा। यह इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के इतिहास में दोबारा बढ़ाई गई सर्वाधिक दूध क्रय दर है। संघ द्वारा दूध क्रय दर में वृद्धि करने एवं निर्धारित तिथियों में भुगतान होने पर दुग्ध उत्पादकों में जहां खुशियों की लहर दौडने लगी है वहीं दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को आर्थिक लाभ होने के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय में रूचि भी बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों को नियत तिथियों 03 तारीख, 13 तारीख और 23 तारीख में अनिवार्य रूप से नियमित भुगतान किया जा रहा है। एमपी स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. संजय गोवाणी ने कहा कि राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य हुए सहकार्यता अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार इस वर्ष इंदौर दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में 550 नवीन दुग्ध समितियों का गठन किया जा रहा है। इंदौर दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बलबीर शर्मा ने बताया कि इस कदम से 14000 पशुपालकों को दुग्ध संघ से जोड़ा जा रहा है, जो इस दूध क्रय दर वृद्धि का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करेंगे।

99 एकड़ प्रॉपर्टी पोर्टल पर नया साइबर फ्रॉड का तरीका

इंदौर। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल 99 एकड़ पर मकान या फ्लैट किराए से डालने वालों को निशाना बनाने के लिए साइबर ठगों ने एक नया तरीका अपनाया है।

ठगी का तरीका- जैसे ही कोई व्यक्ति किराए का विज्ञापन डालता है, तुरंत ठग कॉल करके कहते हैं कि उन्हें वही मकान किराए पर चाहिए। वे खुद को सरकारी अधिकारी बताकर भरोसा दिलाते हैं। बातचीत में वे कहते हैं कि "हम 8 दिन बाद शिफ्ट होंगे, पहले पेमेंट करना है, आप कितना एडवांस लेंगे?"

सामान्यतः लोग 1+1 (एक एडवांस + एक रनिंग) की शर्त बताते हैं। इसके बाद ठग कहते हैं: "हम पेमेंट आपके अकाउंट में एड करेंगे, इसके लिए ओटीपी आएगा, वो हमें बताइए।" असल में यह ओटीपी बैंकिंग/UPI लिंक्ड फ्रॉड का हिस्सा होता है, जिससे खाता खाली किया जा सकता है।

सावधान रहें

किसी भी हालत में OTP, लिंक, QR Code या UPI PIN किसी को न बताएं। "सरकारी अधिकारी" या "फर्जी ID" दिखाकर झांसा दिया जा सकता है। केवल किरायेदार को आमने-सामने देखकर ही एडवांस लें। सभी को यह समझना चाहिए कि पेमेंट receive करने के लिए OTP की जरूरत नहीं होती।

आज का वाक़िया

आज 99 एकड़ पोर्टल पर लिस्टिंग डालते ही ऐसा ही मामला सामने आया।

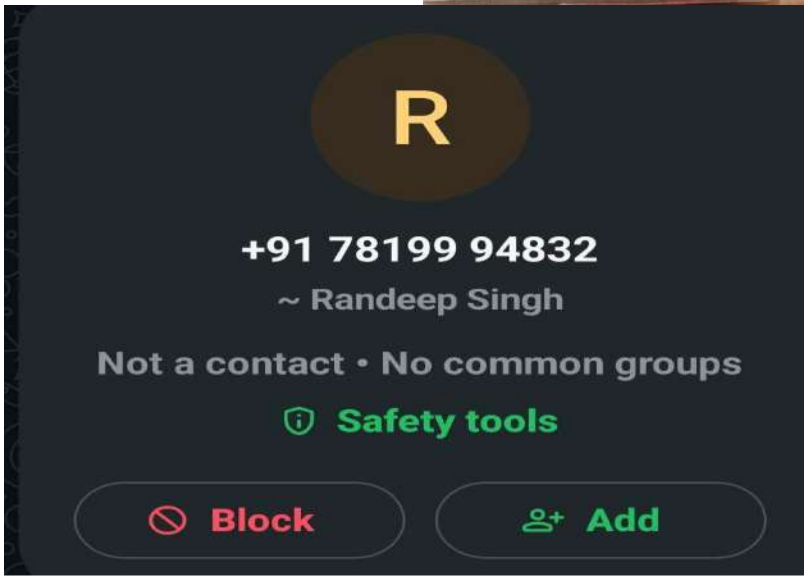

सतर्कता से ठग की चाल पहचान ली गई और किसी वित्तीय नुकसान से बचा गया।

संदेश

सभी प्रॉपर्टी मालिक और आमजन साइबर ठगों से सावधान रहें। ऐसे किसी भी संदिग्ध कॉल की तुरंत शिकायत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने में करें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोलकाता में निवेश अवसरों पर जोर दिया, स्वदेशी विकास, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत की राह पर मध्य प्रदेश का संकल्प साझा किया

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कोलकाता में आयोजित एक महत्वपूर्ण इंटरेक्टिव सेशन में राज्य में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की और इसे विकसित भारत की दिशा में एक बड़े अवसर के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में कोलकाता का योगदान केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और विचारधारात्मक नेतृत्व के रूप में भी महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग दो सौ वर्ष पूर्व बंगाल की धरती से यह विचार उभरा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और आज वही सपना आत्मनिर्भरता, नवाचार और स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से साकार हो रहा है। डॉ. यादव ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने ब्रिटिश शासन की कठिन परिस्थितियों में युवाओं को प्रेरित किया और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका का स्मरण करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने भाजपा की नींव रखी और संविधान में धारा 370 का विरोध कर राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 को समाप्त किए जाने को देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया, जिससे जम्मू-कश्मीर में वर्षों से चल रही हिंसा और अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायता मिली। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से उन 40 हजार से अधिक लोगों को राहत मिली जिन्हें आतंकवाद और संघर्ष के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी रेखांकित किया कि भारत आज स्वामी विवेकानंद के आदर्शों के अनुरूप स्वदेशी उत्पादों, आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि और अन्य क्षेत्रों में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 18 नई नीतियों को लागू किया है, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता, सुशासन, तकनीकी नवाचार और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में न केवल उद्योगों के लिए उत्कृष्ट आधारभूत संरचना उपलब्ध है, बल्कि शांति और सामाजिक सौहार्द की वजह से भी निवेशकों को सुरक्षा और स्थिरता मिलती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश 'शांति का टापू' है, जहाँ हड़ताल जैसी घटनाएँ नहीं होतीं और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलती है। उन्होंने धार जिले में प्रधानमंत्री मित्र पार्क के निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इसका शिलान्यास स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाला ऑर्गेनिक कॉटन उगाया जाता है, जो कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बंगाल के गंगा सागर से लेकर मध्य प्रदेश की नदियों के संगम की सुंदरता का उल्लेख करते हुए बताया कि यह प्राकृतिक संपदा भी व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, युवाओं को रोजगार के अवसर और स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वे मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियाँ स्थापित करें ताकि देश आर्थिक रूप से मजबूत होकर 'सोने की चिड़िया' बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके। अंत में उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर निवेशकों को सहज और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएगी, जिससे समृद्धि, रोजगार और राष्ट्रीय विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

संघ की राह पर चलती दिखेगी मध्यप्रदेश कांग्रेस, जिला अध्यक्ष प्रभात फेरी, श्रमदान और गौ सेवा जैसे कार्यक्रमों से बनाएंगे जनता से जुड़ाव

भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस संगठन ने एक नया प्रयोग करने की तैयारी की है। अब कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की तरह जनसंवाद और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में पैठ बनाने की रणनीति अपनाएगी। इसी कड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रभात फेरी निकालते, श्रमदान करते और गौ सेवा जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते नजर आएंगे। यह कदम कांग्रेस की परंपरागत राजनीतिक कार्यशैली से अलग एक नया प्रयास माना जा रहा है, जिससे संगठन को दृह्ह्डुह्यह्यह्ह्नश्शह्लह्य स्तर पर मजबूती मिलेगी। राज्य में पहली बार कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक समझ, संगठनात्मक रणनीति और विचारधारा के साथ-साथ सेवा कार्यों को भी शामिल किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभात फेरी, श्रमदान और गौ सेवा जैसे कार्यक्रमों को विशेष रूप से शामिल किया गया है ताकि पार्टी के पदाधिकारी समाज में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जनता के बीच भरोसा और अपनापन कायम कर सकें। मिली जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा महाराष्ट्र के वर्धा स्थित एक संस्था के साथ चर्चा कर तैयार की जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया जाएगा कि समाज के बीच किस तरह काम करें, पार्टी की पैठ कैसे बढ़ाई जाए और स्थानीय मुद्दों से जुड़कर संगठन को मजबूत कैसे बनाया जाए। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि सेवा और संवाद के माध्यम से जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और पार्टी की पकड़ मजबूत होगी।

इस प्रशिक्षण से पहले गुजरात में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मध्यप्रदेश के नेता भी हिस्सा लेंगे। गुजरात में होने वाले प्रशिक्षण से अनुभव और रणनीति साझा की जाएगी ताकि मध्यप्रदेश में इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। संभावना है कि मध्यप्रदेश में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित होगा। सूत्रों के अनुसार, इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से राहुल गांधी भी शामिल होंगे। उनकी उपस्थिति से प्रशिक्षण को विशेष महत्व मिलेगा और संगठन को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। कांग्रेस का यह प्रयास न केवल संगठनात्मक मजबूती का संकेत है, बल्कि जनहित में सेवा कार्यों के माध्यम से समाज से जुड़ने का नया तरीका भी है। अब देखना होगा कि यह प्रयोग किस हद तक सफल होता है और जनता के बीच कांग्रेस की छवि को किस तरह आकार देता है।

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई में RES उपयंत्री रिश्वत लेते पकड़ा गया, ठेकेदार से मूल्यांकन रिपोर्ट बनाने के लिए मांगी थी घूस

बुरहानपुर। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार तेज बनी हुई है, फिर भी घूसखोरी के मामलों में कमी नहीं आ रही। आए दिन अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुरहानपुर जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ लोकायुक्त पुलिस ने ऋश्वस् विभाग के उपयंत्री महेंद्र कोठारी को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। समाचार लिखे जाने तक आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी थी। मामला जिले की जनपद पंचायत खकनार के ग्राम हिंगना से जुड़ा है। यहाँ एक ठेकेदार द्वारा प्रवेश द्वार निर्माण का कार्य किया गया था, जिसकी मूल्यांकन रिपोर्ट बनाने के एवज में उपयंत्री ने 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। ठेकेदार ने बताया कि पहले 8 हजार रुपये की पहली किश्त दे दी थी, और आज 12 हजार रुपये की दूसरी किश्त देते समय उपयंत्री को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। बताया गया है कि यह रिश्वत चाय की दुकान पर दी जा रही थी, तभी लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए उपयंत्री को पकड़ लिया। ठेकेदार राजू वाघमारे ने उपयंत्री की घूस मांगने की शिकायत पहले ही लोकायुक्त इंदौर से कर दी थी। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया और आज दूसरी किश्त लेते समय आरोपी को पकड़ लिया। लोकायुक्त इंस्पेक्टर सचिन पटेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जनता में आक्रोश है, वहीं अधिकारी कर्मचारियों की घूसखोरी के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई से एक संदेश भी दिया गया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठेकेदारों और आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि ऐसे मामलों में शिकायत करें ताकि दोषियों को कानून के तहत दंडित किया जा सके।

बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में सांसद-विधायकों को स्थान नहीं मिलेगा, नए चेहरों को प्राथमिकता- मंत्री का बयान

भोपाल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत आगामी कार्यकारिणी में वर्तमान सांसदों और विधायकों को स्थान नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि संगठन में नए चेहरों को जगह देने के लिए यह बड़ा निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार, अभी तक कार्यकारिणी में सात सांसद और एक कैबिनेट मंत्री सहित छह विधायक पदाधिकारी के रूप में शामिल हैं, जबकि 14 प्रदेश उपाध्यक्ष, पाँच महामंत्री और 13 प्रदेश मंत्री जैसे पदों पर कार्यरत हैं। आगामी कार्यकारिणी में इन्हें स्थान दिए बिना संगठन में बदलाव किया जाएगा ताकि नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिल सके। जानकारी के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी का गठन पितृपक्ष के बाद किया जाएगा। इसके लिए एक स्पष्ट फॉर्मूला तैयार किया गया है, जिसमें संगठनात्मक संतुलन और समन्वय का ध्यान रखा जाएगा। भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कार्यकारिणी का गठन प्रदेश अध्यक्ष का विशेष अधिकार है, लेकिन इसे केंद्र नेतृत्व के निर्देश और सभी कार्यकर्ताओं के समन्वय से अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसे कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा और किसे नहीं, इसका फैसला संगठनात्मक सहमति से लिया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मुरैना सांसद संध्या राय, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीक, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, अनुसूचित जाति मंत्री नागर सिंह चौहान और आलोट विधायक चिंतामण मालवीय कार्यरत हैं। वहीं प्रदेश महामंत्री में राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, जतारा विधायक हरिशंकर खटीक और भोपाल पश्चिम विभाग भगवान दास सबनानी शामिल हैं। प्रदेश मंत्री में सागर सांसद लता वानखेड़े, जबलपुर सांसद आशीष दुबे और जयसिंह नगर विधायक मनीषा सिंह कार्यरत हैं। इसके अलावा संयुक्त कोषाध्यक्ष के पद पर उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन का अखाड़ा मौजूद हैं। इसी तरह संगठन के सात मोर्चा संगठनों में से तीन की कमान सांसदों के पास है, जबकि एक की जिम्मेदारी मंत्री संभाल रहे हैं। राज्यसभा सांसद नारोलिया महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, सांसद दर्शन चौधरी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जबकि एक कैबिनेट मंत्री ओबीसी मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकारिणी में बदलाव का निर्णय संगठन के भविष्य और नए नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

यह कदम भाजपा की संगठनात्मक मजबूती और नए कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश कार्यकारिणी का यह नया स्वरूप पार्टी की रणनीति को किस तरह आकार देता है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करता है।

शिक्षा केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन नही

शिक्षक का व्यवहार छात्र के प्रति और शिक्षक के प्रति छात्र का व्यवहार ठीक होना चाहीए

उज्जैन।

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष और कौशल विकास मंत्री श्री इंदरसिंह परमार के मुख्य आतिथ्य में ग्राम हासामपुरा के समीप अवंतिका विश्व विद्यालय में आयोजित चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वयं की शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा है, शिक्षक का व्यवहार छात्र के प्रति और शिक्षक के प्रति छात्र का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। यह नीति देश में सर्वप्रथम मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है जिसके परिणाम भी अच्छे आने लगे है। इस नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदरसिंह परमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सच्ची शिक्षा का मूल आधार चरित्र का विकास है। शिक्षा नैतिक बल देती है। शिक्षक का आचरण और व्यवहार शिष्य के जीवन में परिलक्षित होता है। अच्छा शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों को तराशता है। अच्छा नागरिक चरित्रवान व्यक्ति ही बन सकता है। हमें विकसित भारत बनाने के लिए तथा विश्व गुरु बनने के लिए राष्ट्रीय और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना होगा। यह कार्य शिक्षक ही कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से यह संभव हो सकेगा। हमारी प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में ही होना चाहिए। अपनी भाषा में अध्ययन-अध्यापन करने से चिंतन में मौलिकता एवं सृजनात्मकता आती है और विषय अधिक सहजता से ग्रहण होता है। हम अपने दैनिक व्यवहार आदि कार्य में यथा संभव अपनी भाषा का प्रयोग कर अपने व्यवहार में वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण को हम अपनायें। शिक्षा पद्धति में कई नवाचार किये जा रहे है। विकसित भारत बनाने में श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करने से ही संभव है।

शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का समाधान हमारे अंदर ही है। श्री कोठारी ने कहा कि मूल्य परक शिक्षा के अभाव में मनुष्य के चरित्र का निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास संभव नहीं है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को समकालीन संदर्भ में पुनर्स्थापित करने का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। यह नीति व्यक्तित्व निर्माण ,चरित्र विकास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ शिक्षा को जोड़ने का कार्य कर रही है। हमें पंचकोश पर आधारित जीवन यापन कर स्वस्थ और श्रेष्ठ नागरिक बनना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया की ऊंकार मंत्र बोलने से हमारे मन में एक अच्छी अनुभूति होती है। उन्होंने पंचकोश पर कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, प्रणीक, मानसिक, बौद्धिक तथा अध्यात्मिक विकास का होना आवश्यक है। डॉ. कोठारी ने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हुए बताया कि किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण स्वभाव अर्थात चरित्र ही व्यक्तित्व कहलाता है। अपने अनेक उदाहरण सहित प्रेरणादायी वक्तव्य प्रस्तुत किये।

कार्यशाला में अतिथियों ने ज्ञान महाकुंभ प्रयागराज संकल्प पत्र पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यशाला के प्रारंभ में अतिथियों ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप-दीपन किया। इस अवसर पर पाणिनी संस्कृत विश्व विद्यालय के बटुकों द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। इसके बाद विश्व शांति वर्ल्ड पीस प्रार्थना की गई। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार का स्वागत अवंतिका विश्व विद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर श्री संजय धाण्डे ने किया। कार्यशाला के मुख्य वक्ता डॉ. अतुल कोठारी का स्वागत एमआईटी पुणे ग्रुप के प्रोफेसर अनंत चक्रदेव द्वारा किया गया। प्रोफेसर श्री संजय धाण्डे का स्वागत विक्रमविश्व विद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज तथा विशिष्ट अतिथि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के क्षेत्रीय संयोजक श्री ओम प्रकाश शर्मा का स्वागत अवंतिका विश्व विद्यालय के कुलपति प्रो. नितीन राणे ने किया तथा निर्मला ग्रुप ऑफ कॉलेज के आर्क विशप डॉ. सेबिस्टियन वडुकल का स्वागत पाणिनि विश्व विद्यालय के कुलगुरु प्रो. शिव शंकर मिश्र द्वारा किया गया। कार्यशाला में स्वागत उद्बोधन एमआईटी पुणे के प्रो. अनंत चक्रदेव ने दिया। कार्यशाला की विस्तार से जानकारी विक्रमविश्व विद्यालय के कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज ने दी। कार्यशाला में अवंतिका विश्व विद्यालय के कुलाधिपति प्रो. संजय धाण्डे ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन माधव महाविद्यालय के प्रो. जफर मेहमूद ने किया और अन्त में आभार प्रो. नतीन राणे ने प्रकट किया।

फार्मेसी पंजीयन प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन, पूरी पारदर्शिता से नियमानुसार प्रकरणों का करें निराकरणः उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

मध्यप्रदेश स्टेट फार्मेसी परिषद की बैठक संपन्न

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि अब ऑनलाइन प्रणाली से घर बैठे पंजीयन प्रमाणपत्र मेल और डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध होंगे। इससे पंजीयन प्रक्रिया सुव्यवस्थित हुई है और लंबित मामलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यार्थियों के आवेदन अपूर्ण हैं, जिन्हें समय पर पूरा करवाना आवश्यक है।

प्राइवेट विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे सभी विद्यार्थियों की सही जानकारी उपलब्ध कराएँ। यदि गलती छात्रों की है तो उन्हें सुधार हेतु सूचित किया जाए और यदि संस्थान की लापरवाही है तो मान्यता एवं एफिलिएशन पर कार्रवाई करें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल होटल पलाश भोपाल में मध्यप्रदेश स्टेट फार्मेसी परिषद की बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। विकसित और स्वस्थ भारत के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में जून 2025 से अगस्त 2025 तक की कार्यप्रगति की समीक्षा की गई। इसमें 3500 से अधिक नए पंजीयन सफलतापूर्वक पूर्ण हुए, 5800 आवेदन प्रक्रिया में लंबित रहे तथा 1650 आवेदन निजी विश्वविद्यालयों की सूची उपलब्ध न होने के कारण शेष रहे। बताया गया कि संपूर्ण कार्यप्रणाली को अब डिजिटल मोड पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इसमें समग्र आईडी, डिजिलॉकर, विवाह एवं निवास प्रमाणपत्र तथा एफडीए का एकीकरण किया गया है। नई प्रणाली से स्लॉट बुकिंग एवं परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन कराने की आवश्यकता समाप्त होगी और सिस्टम आधारित ऑटो वेरिफिकेशन से प्रमाणपत्र सीधे डिजिलॉकर पर उपलब्ध होंगे। यह पहल परिषद को डिजिटल गवर्नेंस में देश की अग्रणी परिषद बनाएगी।

यातायात जागरूकता की पाठशाला में स्टूडेंट्स ने पढ़ा "राहवीर योजना" की जानकारी का पाठ

इंदौर शहर के यातायात को सुगम, सुरक्षित व सुखद बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। इसी कड़ी में आज दिनाँक को बिरला ओपन माइंड सीबीएसई इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर यातायात के एसीपी श्री मनोज कुमार खत्री के द्वारा विशेष ट्रैफिक अवेयरनेस एवं ट्रैफिक एजुकेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ-साथ स्कूल वाहनों के चालक-परिचालक, शिक्षकों एवं स्टाफ, यातायात प्रधान आरक्षक दीपेंद्र मेहरा ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा शासन की "राहवीर योजना" के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया। कार्यक्रम में एसीपी ट्रैफिक श्री मनोज कुमार खत्री द्वारा सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण, उनसे बचाव के उपाय, एवं सड़क पर घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज प्रारंभ करवाने की जिम्मेदारी के महत्व पर जागरूक किया।

संपादकीय

जीएसटीः दरों में कटौती से मिलेगी राहत

सरकार की ओर से हाल में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती के एलान से माना जा रहा था कि इससे आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। उनके पास पैसों की बचत होगी, जिसे वे अन्य जरूरी वस्तुएं जुटाने पर खर्च कर सकेंगे। मगर इससे पहले कि जीएसटी की नई दरें लागू होतीं, लोगों की जेब पर एक और शुल्क का बोझ पड़ गया है। आनलाइन माध्यम से भोजन की आपूर्ति करने वाली कुछ कंपनियों ने अपने मंच शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। यानी आनलाइन भोजन मंगवाना अब महंगा हो जाएगा। इसका असर देशभर के लाखों लोगों पर पड़ेगा।

माना जा रहा है कि 22 सितंबर से आपूर्ति शुल्क पर अठारह फीसद जीएसटी लागू होने पर आनलाइन भोजन मंगाने पर खर्च और बढ़ सकता है। ऐसे में यह सवाल भी अहम हो गया है कि सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत जो कदम उठाया है, क्या वास्तव में उसका लाभ उभोक्ताओं को मिल पाएगा या नहीं?

खबरों के मुताबिक, आनलाइन बुकिंग के माध्यम से भोजन परोसने वाली एक मुख्य कंपनी ने चुनिंदा बाजारों में अपना मंच शुल्क जीएसटी सहित पंद्रह रुपए कर दिया है। इसकी एक अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने भी अपना मंच शुल्क बढ़ाकर 12.50 रुपए (जीएसटी को छोड़कर) कर दिया है, जबकि एक अन्य कंपनी ने व्यापक उद्योग रुझानों के अनुरूप अपना मंच शुल्क संशोधित करके दस रुपए प्रति आर्डर कर दिया है। भोजन आपूर्ति कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि 22 सितंबर से जब आपूर्ति शुल्क पर अठारह फीसद जीएसटी लागू हो जाएगा तो उपयोगकर्ताओं पर प्रति आर्डर लगभग दो रुपए से

लेकर ढाई रुपए से ज्यादा तक अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

जानकारों का कहना है कि जीएसटी में बदलाव से भोजन तैयार करने की लागत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उपभोक्ताओं पर शुल्क का अतिरिक्त बोझ डालने का औचित्य समझ से परे है। ऐसे में इन कंपनियों द्वारा मंच शुल्क में एक साथ की गई बढ़ोतरी खाद्य वितरण क्षेत्र में महंगाई के बढ़ते रुझान को रेखांकित करती है, जिससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या लाखों ग्राहकों के लिए सामर्थ्य और सुविधा अब भी साथ-साथ चल सकती हैं?

सरकार का तर्क है कि जीएसटी दरों में कटौती और इनके सरलीकरण से न केवल आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि घरेलू मांग भी बढ़ेगी, छोटे और बड़े उद्यमों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे उनके खर्च की क्षमता भी बढ़ेगी। सरकार के इस फैसले को अमेरिकी शुल्क की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल, सरकार का जोर घरेलू मांग और खपत बढ़ाने पर है।

कर में राहत से लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप खपत में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे अमेरिकी शुल्क का प्रभाव कम होगा। मगर यह तभी संभव होगा, जब जीएसटी दरों में कटौती का लाभ वास्तव में उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। अगर एक तरफ कर कम किया जाता है और दूसरी तरफ बढ़ा दिया जाता है तो जाहिर है कि मांग और खपत बढ़ने की उम्मीदों पर भी धुंधलका छाया रहेगा। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीएसटी सुधारों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और जिन उत्पादों पर कर बढ़ा है, उसका बोझ सीधा उपभोक्ता पर न डाला जाए।

अतिवृष्टि से खुल गई देश के विकास की तस्वीर की पोल

> राजनीतिक दलों को इसकी परवाह नहीं है। दीर्घकालीन नीतियों के बाद अल्पकालीन नीतियों से विनाश हो रहा है। नीतियां बनाते वक्त दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं किया गया। देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां नदी-नालों के प्राकृतिक स्त्रोतों का अतिक्रमण नहीं किया गया हो। गंगा सहित देश की हर नदी आधुनिक विकास की नाकामियों से उपजे प्रदूषण की मार झेल रही हैं। सरकारी आकंडों में देश में वनों का विकास दर्शाया जाता है। इसके विपरीत जंगलों की कटाई का खेल जारी है। बर्बादी का यह आलम राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से उत्पन्न हुआ है। सत्ताधारी दलों ने वोट बैंक की राजनीति में विकास की दौड़ को अंधा बना दिया है। जब कभी अदालतों के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाते हैं, तो नेता बीच में आ जाते हैं। यही वजह है कि देश में एक भी बड़ा शहर अतिक्रमण से अछूता नहीं रहा है। अतिक्रमियों ने नदियों, जंगल बल्कि पहाड़ों तक को नहीं छोड़ा है। देश के प्राकृतिक संसाधनों पर दोहरी मार पड़ रही है।

योगेंद्र योगी

देश के विकास की असली तस्वीर इस बार मानसून में दिल्ली में देखने को मिली है। देश की राजधानी बारिश और यमुना के जलस्तर बढने़ से हाल-बेहाल हो गई। राजधानी की जिंदगी पर ब्रेक लग गया। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश से देश के अन्य राज्य कितने हाल-बेहाल होंगे। यह समस्या नई नहीं है। देश में हर साल मानसून के दौरान लगभग सभी राज्यों में यही हाल होता है। विकास का वादा और दावा करने वाली सरकारें और राजनीतिक दल सिर्फ हवाई किले बना कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। इसमें कोई भी दल पीछे नहीं हैं। ऐसे मौकों पर नेता गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं और जिम्मेदारी को पूववर्ती सरकारों के पाले में डाल कर बरी हो जाते हैं। बाढ़ और उसके जैसे हालात से साबित हो गया है कि नेताओं को देश के आम लोगों की जिन्दगी और मौत की फिक्र नहीं है। यह हालत हुई है देश में वोट बैंक की राजनीतिक के कारण। इसके कारण अतिक्रमण और प्रकृति से छेड़छाड़ की कीमत हर साल चुकानी पड़ रही है। यह समस्या विकराल होती जा रही है।

दिल्ली में यमुना नदी की बाढ़ एक पुरानी समस्या है, जो हर मॉनसून में तबाही मचा देती है। सितंबर के पहले हफ्ते में भारी बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोडने़ से यमुना का जलस्तर खतरे के पार चला गया। पुरानी दिल्ली रेलवे ब्रिज पर 205 मीटर (खतरे का स्तर) पार कर 207.48 मीटर तक पहुंच गया। इससे 10,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मयूर विहार, यमुना बाजार, मजनू का टीला जैसे इलाके डूब गए, ट्रैफिक जाम लग गया।

पुराने रिकॉर्ड्स के अनुसार, 1956 से पहले यमुना हर साल ट्रांस-यमुना इलाकों को डुबो देती थी। 1978 में सबसे भयानक बाढ़ आई, जब जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचा और अलीपुर ब्लॉक, मॉडल टाउन जैसे इलाके डूब गए। इसमें 18 मौतें, 10 करोड़ का नुकसान। उसके बाद 1988, 1995, 1998 में हाई फ्लड्स आए, लेकिन इम्बैंकमेंट (बांध) बनने के बाद भी समस्या बनी रही।

1956 से पहले ऐसा कम होता था, लेकिन अब इम्बैंकमेंट ने जगह कम कर दी। वर्ष 2023 में फ्लडप्लेन अतिक्रमण मुख्य वजह था। नदी का पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। मलबा डालने से बेड ऊंचा हो गया। यमुना में गाद जमा हो गई और नदी उथली हो गई। दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण अतिक्रमण रोकने में नाकाम रहे। लोगों और बिल्डर्स ने फ्लडप्लेन पर अवैध कॉलोनियां बना ली। साल 2023 के बाद भी फ्लडप्लेन पर निर्माण (रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट) ड्रेन क्लीनिंग और डिसिल्टिंग का इंतजाम नहीं किया गया। केंद्र सरकार (जल शक्ति मंत्रालय) बैराज ऑपरेशन में समन्वय की कमी बाढ़ की हालात का बड़ा कारण रहा।

देश में बाढ़ के हालात को लेकर सरकारें नींद में गाफिल हैं। सुप्रीम कोर्ट सरकारों को जगाने का प्रयास कर रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्य बीते कुछ दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित राज्यों में अवैध पेड़ कटाई के प्रथम दृष्ट्या प्रमाण पर चिंता जताई

है। कोर्ट ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर की सरकारों को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का संकेत है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इसके कारणों का पता लगाएं।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। फ्लैश फ्लड यानी बादल फटने की घटनाओं, भारी बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं में सैकड़ों जानें गई हैं। ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भारतीय मौसम विभाग ने चार राज्यों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। अगस्त 2025 में उत्तर-पश्चिम भारत में 265 मिमी बारिश हुई, जो 2001 के बाद सबसे ज्यादा है। आईएमडी ने सितंबर में 109 प्रतिशत ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। अगस्त 2025 में उत्तर-पश्चिम भारत में वर्ष 2001 के बाद सबसे ज्यादा 265 मिमी बारिश हुई, जो रिकॉर्ड तोडने़ वाली है।

भारतीय मौसम विभाग ने सितंबर 2025 के लिए सामान्य से 109 प्रतिशत ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है, जिससे और तबाही का खतरा बढ़ गया है। अतिवृष्टि से हिमाचल प्रदेश में 320 मौतें, 788 सड़कें बंद, 2174 ट्रांसफॉर्मर डैमेज हुए। कुल 23 फ्लैश फ्लड, 19 क्लाउडबर्स्ट, 16 भूस्खलन हुए। उत्तराखंड में धराली, उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड हुआ। जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन से 30 से अधिक मौतें और 20 लोग घायल हुए। जम्मू में तवी नदी का ब्रिज गिर गया। पंजाब में ब्यास, सतलुज, रावी उफान पर हैं। इससे 3 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। पंजाब के 7 जिले बाढग्रस्त हैं।

अतिवृष्टि के मौजूदा हालात के लिए मौसम की मार नहीं बल्कि विकास की गलतियां जिम्मेदार हैं। मौसम पूर्वानुमान बेहतर हो रहा है, लेकिन चेतावनियों पर प्रतिक्रिया न देना बड़ी समस्या है। वेल डिफाइंड सिस्टम (जैसे चक्रवात) पर 2-4 दिन पहले अलर्ट संभव, लेकिन मेजोस्केल सिस्टम (10-100 किमी) में बादल 15 किमी ऊपर बनकर 1 घंटे में भारी बारिश कर देता है। रडार-सैटेलाइट से पता चलने पर सिर्फ 10-15 मिनट मिलते हैं। वक्त रहते चेतावनी के लिए ऑल वेदर कम्युनिकेशन सिस्टम, हैम रेडियो से कम्युनिटी रेडियो, स्थानीय ट्रेनिंग और ज्यादा रडार लगाने पड़ेंगे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक कम और मानवजनित ज्यादा जैसी आपदा का प्रमुख कारण देश के विकास मॉडल का प्रकृति से खिलवाड़ करके बनाया जाना है।

राजनीतिक दलों को इसकी परवाह नहीं है। दीर्घकालीन नीतियों के बाद अल्पकालीन नीतियों से विनाश हो रहा है। नीतियां बनाते वक्त दूरदर्शिता का इस्तेमाल नहीं किया गया। देश का एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां नदी-नालों के प्राकृतिक स्त्रोतों का अतिक्रमण नहीं किया गया हो। गंगा सहित देश की हर नदी आधुनिक विकास की नाकामियों से उपजे प्रदूषण की मार झेल रही हैं। सरकारी आकंडों में देश में वनों का विकास दर्शाया जाता है। इसके विपरीत जंगलों की कटाई का खेल जारी है।

बर्बादी का यह आलम राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से उत्पन्न हुआ है। सत्ताधारी दलों ने वोट बैंक की राजनीति में विकास की दौड़ को अंधा बना दिया है। जब कभी अदालतों के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाए जाते हैं, तो नेता बीच में आ जाते हैं। यही वजह है कि देश में एक भी बड़ा शहर अतिक्रमण से अछूता नहीं रहा है। अतिक्रमियों ने नदियों, जंगल बल्कि पहाड़ों तक को नहीं छोड़ा है। देश के प्राकृतिक संसाधनों पर दोहरी मार पड़ रही है।

एक तरफ अतिक्रमण और दूसरी तरफ अतिदोहन का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसके अलावा शहरों के अनियोजित विकास ने हालत करेला और नीम चढ़ा जैसी कर दी है। आश्चर्य यह है कि इतना विनाश हर साल होने के बावजूद नेताओं की नींद नहीं खुल रही है। वोट बैंक के लिए बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जान-माल का होने वाला नुकसान अभी भी राजनीतिक दलों के एजेंडे से बाहर है। राजनीतिक दलों को शायद समझ तभी आएगी, जब देश के आम लोग सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे।

जॉब इंटरव्यू से पहले ये होमवर्क करना न भूलें

जब आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इसके लिए होमवर्क करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा होमवर्क आपके भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करता है और आप सफलता हासिल करते हैं।

फर्स्ट इम्प्रेशन

इंटरव्यू के लिए फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है। इसलिए ऐसे कपड़ों का चयन करें जिसमें आप ज्यादा स्मार्ट दिखते हों। इससे लोगों का ध्यान आपकी ओर जाएगा। यह भी ध्यान रखें कि उस कपड़े में आप खुद को कंफर्ट महसूस करें। आपके कपड़े का कलर सौम्य और प्रभावशाली हो। इसके लिए आप काला, सफेद, ग्रे लाइट या डार्क शेड के अलावा भूरा, ब्लू और मटमैले कलर के कपड़ों का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं।

स्ट्रांग परफ्यूम न लगाएं

पुरुषों के लिए यह जरूरी है कि वे क्लीन शेव हों। किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते, तो दाढ़ी ट्रिम होनी चाहिए, बालों को स्टाइलिश रखें। वह महिलाओं के लए जरूरी है कि वे लाइट मेकअप करें। बाल बंधे हों तो ज्यादा अच्छा है। एक बात का ध्यान दें कि लंबे नाखून पुरुष और महला दोनों के ही नहीं होने चाहिए। यदि परफ्यूम है तो वह स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, आपके जूते अच्छी हालत में होने चाहिए, जूते आवाज न करें।

बाएं हाथ में रखें फाइल

मीटिंग या इंटरव्यू में हमेशा समय से पहले पहुंचें और फ्रंट ऑफिस को अपने आने का कारण बताएं। जब तक आपको अंदर न बुलाया जाए, शांति से अपनी जगह पर बैठे रहें। बुलाने पर तेजी से कदम बढ़ाते हुए जाएं, अपने बैग या फाइल को ठीक तरीके से हैंडल करें। इसे बांए हाथ में पकड़ना अच्छा होगा क्योंकि दाहिने से शेक हैंड्स करना होता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें।

हाथ मिलाना बाध्यता नहीं

यह जरूरी होता है कि आप सामने वाले से हाथ मिलाएं, लेकिन इसे बाध्यता नहीं समझना चाहिए, टेबल के ऊपर हाथ न रखें। अगर आप पुरुष हैं और महिला से मुलाकात हो रही है, तो आप खुद हाथ आगे न बढ़ाएं, इंतजार करें।

पॉजिटिव एहसास कराएं

इंटरव्यू समाप्त होने पर सामने वाले को धन्यवाद कहें और उसे इस बात का एहसास करवाएं कि आप पॉजिटिव रिस्पांस सुनने के लिए तैयार हैं। जाते वक्त यह ध्यान में रखें कि आपके अंदर आने के दौरान गेट खुला था या बंद, गेट जिस अवस्था में था, उसी अवस्था में करके ही बाहर निकलें।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मौका देती है ये स्कॉलरशिप

विदेश में पढ़ाई करना बेहद ही खर्चीला होता है, जिसकी वजह से हर कोई वहां पढ़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए स्कॉलरशिप ही एकमात्र वो जरिया होती हैं, जिनके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी विदेश में पढ़ने का रास्ता खुलता है।

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज की जब भी बात होती है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जिक्र जरूर होता है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में मौजूद ये यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज के लिए दुनियाभर में फेमस है। हर साल बड़ी संख्या में छात्र यहां पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही दाखिला मिल पाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फीस भी बहुत ज्यादा है। अगर भारतीय रुपये में बात करें तो यहां की फीस लाखों में है।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में औसतन फीस 83 हजार डॉलर (लगभग 68 लाख रुपये) है। यही वजह है कि यहां ज्यादातर वही लोग पढ़ पाते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। हालांकि, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आम आदमी यहां पढ़ाई नहीं कर सकता है। हार्वर्ड उन्हें भी एक समान मौका देता है। यूनिवर्सिटी में कई सारी स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन है, जो यहां पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों को कौन सी स्कॉलरशिप मिलती हैं।

बौस्टनी एमबीए हार्वर्ड स्कॉलरशिप

अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ये स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाती है, जिनका पढ़ाई का बैकग्राउंड काफी ज्यादा मजबूत है। हार्वर्ड एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन होने के बाद ही छात्र इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हें इंटरव्यू देना होगा। इस स्कॉलरशिप के तहत छात्रों की 75 फीसदी ट्यूशन फीस कवर हो जाती है। इसके जरिए रहने और यात्रा का भी खर्च कवर होता है।

होरेस डब्ल्यू गोल्डस्मिथ फेलोशिप

इस स्कॉलरशिप के लिए छात्र का बैचलर डिग्री पूरा किया होना जरूरी है। उसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उम्मीदवार ने अगर किसी नॉन प्रॉफिट संस्था में फुल-टाइम लीडरशिप की भूमिका में काम किया होगा तो उसे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिल माना जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू होता है। हार्वर्ड में एमबीए की पढ़ाई कर रहे फर्स्ट ईयर के 7 से 10 छात्रों को 10 हजार डॉलर स्कॉलरशिप के तौर पर मिलते हैं। एमबीए के लिए अप्लाई करते समय ही उम्मीदवार की फाइल स्कॉलरशिप के लिए पहुंच जाती है। फिर उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर स्कॉलरशिप मिलती है।

रॉबर्ट एस. कपलान (एमबीए 1983) लाइफ साइंसेज फेलोशिप

हार्वर्ड में पढ़ने के लिए इस स्कॉलरशिप को उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाता है, जिन्होंने बैचलर डिग्री पूरी की है। उनके काम वर्क एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ लाइफ साइंसेज क्षेत्र में बेहतरीन योग्यता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाता है। एमबीए के लिए अप्लाई करते समय उम्मीदवार के नाम पर स्वतः ही स्कॉलरशिप के लिए विचार किया जाता है। ये स्कॉलरशिप 10 एमबीए स्टूडेंट्स को मिलती हैं। दो साल में 20 हजार डॉलर छात्र को स्कॉलरशिप के तौर पर मिलते हैं।

आगा खान स्कॉलरशिप

अगर किसी स्टूडेंट्स की पढ़ाई का बेहतरीन इतिहास रहा है, तो वह इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। ये स्कॉलरशिप विकासशील देशों के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जिन्हें वास्तव में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत होती है। इस स्कॉलरशिप को पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए दिया जाता है। अगर किसी छात्र के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। साथ ही वह विविध गतिविधियों में भाग लेता रहा है तो उसे स्कॉलरशिप के लिए योग्य माना जाएगा। ये स्कॉलरशिप मास्टर स्तर के कोर्सेज की पूरी अवधि के लिए प्रदान की जाती है और पीएचडी छात्रों को इसे केवल पहले दो वर्षों के लिए दिया जाता है। इसके लिए आगा खान फाउंडेशन की वेबसाइट पर अप्लाई करना होता है।

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिपः

निखत 5-0 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में

नई दिल्ली, एजेंसी। लिवरपूल में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दो बार की वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन ने मंगलवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 51 किग्रा वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल में जापान की युमा निशिनाका को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। निखत के अलावा मीनाक्षी, जदुमणि और अभिनाश जामवाल भी क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। निखत का इस साल का पहला इवेंट 29 साल निखत के लिए यह इस साल का पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। पहले राउंड में जापानी खिलाड़ी ने कड़ा मुकाबला किया, लेकिन निखत ने अपनी लय बनाए रखी और जीत हासिल की। मैच के दौरान युमा ने निखत के रिदम को तोड़ने के लिए अत्यधिक क्लिंचिंग (गले लगाकर रुकने) की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें दो पेनल्टी पॉइंट्स का नुकसान हुआ। निखत ने जापानी खिलाड़ी को कोई मौका नहीं दिया और सर्वसम्मति से जीत हासिल की। 48 KG में मीनाक्षी ने चीनी खिलाड़ी को हराया निखत के अलावा अन्य भारतीय बॉक्सरों ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मीनाक्षी (48 किग्रा) ने चीन की वांग क्यूपिंग को 5-0 से हराया। जबकि जदुमणि (57 किग्रा) ने इंग्लैंड की रीडशॉ रीस को 5-0 से पराजित किया। वहीं, अभिनाश जामवाल (65 किग्रा) ने डोमिनिकन गणराज्य के पीटर यनोआ फर्नांडो डी जीसस को 5-0 से मात देकर अगले दौर में जगह पक्की की।

आर्चरीः

विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन, भारतीय पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग में पदक की दौड़ से बाहर

ग्वांगजू (दक्षिण कोरिया), एजेंसी। तीनों में सबसे अनुभवी ओलंपियन धीरज बोम्मादेवरा को सबसे कठिन ड्रॉ मिला, क्योंकि पहले दौर में उनका मुकाबला पूर्व ओलंपिक चैंपियन मेटे गाजोज से हुआ। भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाजों का विश्व चैंपियनशिप में निराशाजनक प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा और उसके सभी तीरंदाज व्यक्तिगत वर्ग के पदक चरण में जगह बनाने में असफल रहे।भारत के तीनों खिलाड़ियों में राहुल ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने तीसरे राउंड (अंतिम-32) में जगह बनाई, लेकिन शूट-ऑफ में जॉर्जिया के एलेक्जेंडर माचावरियानी से 5-6 (8-10) से हार गए। इस 21 वर्षीय खिलाड़ी ने 5-3 की बढ़त बना ली थी, लेकिन अंतिम दो सेटों में वह लड़खड़ा गए, जिससे एक बार फिर रिकर्व वर्ग में दबाव में भारत की मानसिक कमजोरियां उजागर हो गईं। पहला सेट 28-28 से बराबर करने के बाद राहुल ने दूसरे सेट में 30-30 का शानदार स्कोर बनाया और तीसरे सेट में 28-27 से जीत हासिल कर 5-1 की बढ़त बना ली।

चौथे राउंड में उन्हें केवल ड्रॉ की आवश्यकता थी, लेकिन वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जिससे उनके विरोधी खिलाड़ी को वापसी करने का मौका मिल गया। जॉर्जियाई खिलाड़ी ने पांचवां सेट 28-27 से जीतकर शूट-ऑफ कराया, जहां राहुल ने आठ अंक हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी का स्कोर परफेक्ट 10 था। तीनों में सबसे अनुभवी ओलंपियन धीरज बोम्मादेवरा को सबसे कठिन ड्रॉ मिला, क्योंकि पहले दौर में उनका मुकाबला पूर्व ओलंपिक चैंपियन मेटे गाजोज से हुआ। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय खिलाड़ी को पहला सेट 29-29 से बराबर करने के बाद 2-6 से हार का सामना करना पड़ा।

दूसरे सेट में कड़ी टक्कर हुई, लेकिन गाजोज़ के दो 10 ने उन्हें 29-28 की बढ़त दिला दी। तुर्किए के तीरंदाज ने तीसरे सेट में 29-28 के साथ अपनी बढ़त 5-2 कर ली। धीरज ने चौथा सेट 29-29 से बराबर किया, लेकिन यह गाजोज को जीत से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। भारत के एक अन्य खिलाड़ी नीरज चौहान को उज्बेकिस्तान के बोबराजाबोव बेकजोद से सीधे सेटों में 27-29, 27-28, 26-29 से हार का सामना करना पड़ा।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल

➤पाकिस्तान कर सकता है खेल खराब

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 2026 का पुरुष टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। भारत अपना खिताब बरकरार रखने की कोशिश करेगा जिसने पिछली बार 2024 में बारबाडोस में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता था।

इस टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग लेंगी और 55 मैच खेले जाएंगे। मैच भारत में 5 और श्रीलंका में दो स्थानों पर खेले जाएंगे तथा फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाता है, तो यह मैच कोलंबो में होगा।

बीसीसीआई टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। हालांकि इस साल की शुरुआत में बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ था कि वे दोनों सरकारों के बीच लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण एक-दूसरे के देशों में नहीं खेलेंगे जिसके बाद श्रीलंका को पाकिस्तान के सभी मैचों के आयोजन के लिए सह-मेजबान चुना गया।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आईसीसी ने अभी तक कार्यक्रम तय नहीं किया है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए समय निश्चित रूप से तय कर लिया गया है और सभी भाग लेने वाले देशों को इसकी जानकारी दे दी गई है।

फिलहाल अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए केवल 15 टीमें ही क्वालीफाई कर पाई हैं, जिनमें भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और पहली बार इटली भी शामिल हैं। शेष पांच स्थानों में से दो अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालीफायर से और तीन एशिया और पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालीफायर से निकलेंगे।

सालाना 1 करोड़ की कमाई से बदला हाल

अब हर कोई पूछ रहा बता दो फॉर्मूला

नई दिल्ली, एजेंसी।
सोनिया जैन राजस्थान के झालावाड़ की प्रगतिशील महिला किसान हैं। अपनी सूझबूझ और मेहनत से उन्होंने कृषि व्यवसाय में झंडे गाड़ दिए हैं। सोनिया ने कृषि को भारत में देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। वह डेयरी, हर्बल खेती और अलग-अलग कृषि व्यवसायों से हर साल लगभग 1 करोड़ रुपये कमाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनिया ग्रामीण समुदायों को मजबूत भी कर रही हैं। वह टिकाऊ और फायदे वाली खेती को बढ़ावा देने में जुटी हुई हैं। महिला उद्यमियों की भी मदद कर रही हैं। उन्होंने इनोवेशन, सीधे बाजार में बिक्री और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये भारतीय कृषि को बदलने का काम किया है। वह द लेडी फार्मर ब्रांड के तहत अपने उत्पादों की बिक्री करती हैं। आइए, यहां सोनिया जैन की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। सोनिया की सफलता सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि यह पूरे ग्रामीण समुदाय के लिए मिसाल है।

लोगों को साबित किया गलत

भारत में कृषि को अक्सर चुनौती भरे और कम मुनाफे वाले सेक्टर के रूप में देखा जाता है। लेकिन, राजस्थान की दूरदर्शी महिला किसान सोनिया जैन ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और इनोवेशन से यह साबित किया है कि खेती सिर्फ जीविका का साधन नहीं, बल्कि सफल और मुनाफे वाला व्यवसाय हो सकती है। झालावाड़ की रहने वाली सोनिया जैन आज एक करोड़ रुपये तक की सालाना कमाई कर रही हैं। उनके इस सफर ने कई लोगों को प्रेरित किया है। उनकी सफलता का राज केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है।

इनकम बढ़ाने के लिए अपनाया ये मॉडल

सोनिया जैन ने अपनी आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए कृषि में डायवर्सिफिकेशन को अपनाया। वह पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, चावल और जौ के साथ दालें, तिलहन, और औषधीय पौधे भी उगाती हैं। उनकी खेती में एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा और सफेद मूसली जैसे हर्बल पौधे शामिल हैं। इनकी बाजार में अच्छी मांग है। उन्होंने फूलों की खेती और मसालों का भी उत्पादन किया। इन सबके अलावा, उन्होंने डेयरी फार्मिंग में भी कदम रखा। अपने ब्रांड द लेडी फार्मर के तहत उत्पादों को सीधे बाजार में बेचा। इस मॉडल से उन्होंने बिचौलियों को खत्म किया और किसानों के लिए बेहतर दाम सुनिश्चित किए। उन्होंने 4000 वर्ग मीटर के पॉलीहाउस और नेट हाउस का निर्माण करके उत्पादकता और गुणवत्ता को और बढ़ाया।

चुनौतियों से भरा रहा सफर : सोनिया जैन का सफर चुनौतियों से भरा रहा है। लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी। झालावाड़ में पली-बढ़ी सोनिया ने किसानों की समस्याओं को करीब से देखा था। कम मुनाफा, बिचौलियों पर निर्भरता और आधुनिक तकनीकों की कमी, ये सब इसका हिस्सा थे।। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अपने परिवार की कृषि विरासत को फिर से जिंदा करने का फैसला किया। लेकिन, इस बार एक नए, व्यावसायिक और किसान-केंद्रित मॉडल के साथ। उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपनाया। इसमें जैविक और अजैविक उर्वरकों का सही संतुलन, उन्नत बीज और पानी की बचत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, सीड ड्रिल और स्प्रेयर की मदद से उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती को कुशल और टिकाऊ बनाया।

सोच-समझकर कर रहे खर्च

कर छूट के बाद अतिरिक्त आय को बचत-निवेश में लगा रहे कर्मचारी

मुंबई, एजेंसी।
आयकर में छूट मिलने के साथ नौकरीपेशा कर्मचारी वित्तीय नियोजन पर अधिक ध्यान देने लगे हैं।नईकर व्यवस्था लागू होने के बाद करीब 57 फीसदी लोग अपनी अतिरिक्त आय को बचत और निवेश में लगा रहे हैं।

रोजगार के बारे में सूचना देने वाले मंच नौकरी ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा, वित्त वर्ष 2025-26 की नई कर व्यवस्था लागू होने के छह महीने बाद सालाना 12.75 लाख रुपये तक कमाने वाले पेशेवर सोच-विचारकर खर्च की तुलना में बचत, निवेश और कर्ज चुकाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि, नईकर व्यवस्था को लेकर सभी लोग जागरूक नहीं हैं। नए लोग सर्वाधिक जानकारी रखते हैं। 64 फीसदी लोगों ने लाभों के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कही है।43 फीसदी प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि वे या तो स्पष्ट नहीं हैं या बदलावों से पूरी तरह अनजान हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 30 फीसदी लोग अतिरिक्त आय का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में कर रहे हैं। वहीं, कुछ फीसदी लोग ही अतिरिक्त धन को उपभोग में लगा रहे हैं। इसमें 9 फीसदी अपनी जीवनशैली में सुधार पर खर्च कर रहे हैं, जबकि सिर्फ चार फीसदी यात्रा और अवकाश पर खर्च कर रहे हैं।

यह रिपोर्ट देशभर में 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कमाने वाले 20,000 से अधिक पेशेवरों पर किए गए सर्वे पर आधारित है। इनमें से एक भी लोगों पर टैक्स देनदारी अब शून्य है। रिपोर्ट में उद्योग-वार स्पष्ट अंतर भी उजागर किया गया है। इसमें उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र के 76 फीसदी पेशेवर अपनी अतिरिक्त आय बचाने में सबसे आगे हैं। इसके बाद वाहन (63 फीसदी) और औषधि (57 फीसदी) क्षेत्र के पेशेवर हैं।

तालों व हार्डवेयर के मामले में अलीगढ़ की खास पहचान

एमएसएमई फॉर भारत के आयोजन से मिलेगी मदद

नई दिल्ली, एजेंसी।
भारत की अर्थव्यवस्था में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज का अहम स्थान है। ये छोटे और मध्यम उद्यम न केवल नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर रहे हैं और क्षेत्रीय विकास को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। देशभर में एमएसएमई के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंस तक आसान पहुंच, सप्लाई चेन का आधुनिकीकरण, निर्यात क्षमता, कौशल विकास और नीति सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से विचार-विमर्श के लिए अमर उजाला एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है।

इस कॉन्क्लेव के एजेंडा में भविष्य की फंडिंग, मार्केटिंग व ब्रांडिंग रणनीतियाँ, उभरती तकनीकें, नवाचारी वित्तीय समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व डिजिटल अपग्रेडेशन, महिलाओं की भूमिका, भारत के एमएसएमई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार और ओडीओपी योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने की कोशिश होगी। कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाकर उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना। ओडीओपी योजना के तहत देश के हर जिले से एक विशिष्ट स्थानीय उत्पाद को ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख एमएसएमई में लिंक लॉक्स, हैरिसन लॉक्स और गॉडरेज सप्लायर्स प्रमुख हैं। ये फर्म्स स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लॉक और हार्डवेयर उत्पादों की सप्लाई के जरिए अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं।

अलीगढ़ के तालों की देशभर में पहचान

उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ भारत के औद्योगिक नक्शे पर एक जानामाना नाम है। यहां के एमएसएमई सेक्टर की एक अलग ही पहचान है। यह शहर प्रसिद्ध है अपने अनूठे इंडस्ट्रीज लॉक्स, हार्डवेयर, ब्रास प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए। अलीगढ़ को विशेष रूप से तालों और हार्डवेयर उत्पादों के निर्माण के लिए जाना जाता है। यहां के उत्पाद देशभर में अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर हैं। सरकारी समर्थन के तहत यहां अलीगढ़ लॉक क्लस्टर, टूल रूम, और ओडीओपी योजना कार्यरत हैं। यह एमएसएमई इकाइयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दैनिक रणजीत टाइम्स
जिला एवं तहसील स्तर पर
एजेंसी देना है
अपना बायोडाटा सम्पूर्ण विवरण के साथ हमें प्रेषित करें।
सम्पर्क करें
8224951278 :: 9827068888

जन्मदिन की
अग्रिम शुभ सूचना
"रंजीत टाइम्स" में अब आप अपने या अपने प्रियजनों का जन्मदिन एक दिन पहले ही निशुल्क प्रकाशित करवा सकते हैं!
बस हमें भेजिए: 1 जन्मदिन मनाने वाले की फोटो
2 उसका पूरा नाम- 3 बधाई देने वाले का नाम जन्मदिन के एक दिन पहले ही विज्ञापन भेज दें, ताकि समय रहते प्रकाशित किया जा सके।
भेजने का नंबर (Aditya): 8224951278
रंजीत टाइम्स में आपका विज्ञापन पूरी तरह मुफ्त प्रकाशित किया जाएगा!
अपने जज़्बातों को शब्द दें – सिर्फ रंजीत टाइम्स के साथ।
टीम रंजीत टाइम्स- "आपका अपना अख़बार, आपकी आवाज़"
रणजीत टाइम्स

एक बच्चे को जन्म देने वाली मां नागिन के सामान है: यति नरसिंहानंद

बोले- नारियों का सम्मान न करने वाले को जीने का अधिकार नहीं, ज्यादा बच्चे पैदा करें

गाजियाबाद (एजेंसी)। शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने मुजफ्फरनगर के गांधी नगर में श्यामा-श्याम मंदिर में मां बगलामुखी महायज्ञ कर रहे हैं। महायज्ञ के दूसरे दिन उन्होंने श्रीमद्भगदगीता के आधार पर प्रवचन करते हुए कहा- जो समाज या व्यक्ति अपनी मां, बहन, बेटी, पत्नी सहित नारियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं होता। एक बच्चे को जन्म देने वाली मां नागिन के समान है। महायज्ञ में उनके साथ उनके शिष्य यति अभयानंद ,यति धर्मानंद, डॉ योगेंद्र योगी, मोहित बजरंगी भी हैं। महायज्ञ के पुरोहित पंडित सनोज शास्त्री हैं।

नारियों का सम्मान न करने वाले को जीने का अधिकार नहीं

इसका सबसे बड़ा प्रमाण महाभारत का युद्ध है। जो एक नारी महारानी द्रौपदी के अपमान के प्रतिशोध के लिए योगेश्वर श्रीकृष्ण द्वारा रचाया गया था। हस्तिनापुर की राजसभा में जितने भी गणमान्य बैठ कर द्रौपदी का अपमान देख रहे थे, उन सभी को योगेश्वर ने मिटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी के अपमान का दंड केवल कौरवों को मिला।इसका दंड पांडवों को भी भुगतना पड़ा। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने पांडवों को भी उनकी कायरता का इतना कठिन दंड दिया था कि उनके परिवार में उन पांच भाइयों के अतिरिक्त केवल एक बच्चा जीवित बचा था, जो महाभारत के समय अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में था।

मां का तो दोष है ही, पिता का भी कम दोष नहीं है

यति नरसिंहानंद बोले– एक बेटे के होने से तो दो बेटे का न होना ही अच्छा है। महायज्ञ के दूसरे दिन यति नरसिंहानंद ने कहा– महायज्ञ के दौरान उन्होंने कहा– एक छोटी सी बात हवन कुंड की अग्नि को साक्षी मानकर आज कहना चाहता हूं कि आजकल हमारे घरों में हो क्या रहा है... एक बेटा, एक बेटा और एक बेटी। अगर किसी के पहला बेटा हो जाता है तो वो दूसरा बच्चा करना नहीं चाहता। इसमें उनकी मां का तो दोष है ही, पिता का भी कम दोष नहीं है, इसलिए बहन बेटियों अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, तभी सनातन धर्म बचा रहेगा।

प्रगतिपथ पर तेजी से गतिमान है मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. यादव

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश प्रगति पथ पर तेजी से गतिमान है। उन्होंने कहा कि रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के विजन को आत्मसात कर मध्यप्रदेश अपनी युवा शक्ति एवं उद्योग हितैषी नीतियों के साथ भारत के मानचित्र पर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी कड़ी में बुधवार को कोलकाता में मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र में निवेशकों से

मुख्यमंत्री का कोलकाता में निवेशकों से सीधा संवाद

सीधा संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपार निवेश से ही मध्यप्रदेश में एक समृद्ध परिवेश का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कोलकाता के नेता जी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

एमपी में सब कुछ है, आप यहां से बैठे-बैठे वहां बिजनेस कर लेंगे...

निवेशकों को एमपी लाने के लिए सीएम मोहन यादव लगातार प्रयासरत हैं। अब कोलकाता में उद्योगपतियों से उन्होंने वन टू वन चर्चा की है। उन्होंने बंगाल के निवेशकों-उद्योगपतियों को बताया कि मध्यप्रदेश में उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। वे चाहें तो बंगाल में बैठे-बैठे मध्यप्रदेश में व्यापार और निवेश कर सकते हैं। सरकार आपके व्यापार-निवेश की चिंता करेगी।

भारत की होगी 21वीं सदी– वहीं, सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि आधुनिक समय में कोलकाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वामी विवेकानंद ने लगभग 200 साल पहले बंगाल की माटी से कल्पना कर ली थी कि 21वीं सदी भारत की होगी। यहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के दौर में सबसे कठिन परीक्षा पास कर युवाओं का उत्साह बढ़ाया है।

हाट बाजार में सिकल सेल और टीबी की स्क्रीनिंग कराएं: राज्यपाल श्री पटेल

- सिकल सेल अभियान की अवधि बढ़ाएं

भोपाल (एजेंसी)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि हाट बाजारों में सिकल सेल और टीबी की स्क्रीनिंग शिविर लगाए जाने चाहिए जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की विरल आबादी तक पहुंच हो सके। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जाँच के 100 दिवसीय अभियान की उपलब्धियां प्रभावी है और अभियान को 125 दिन तक बढ़ाया जाना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल राजभवन के जवाहर खण्ड में बुधवार को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष और जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर जनजातीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आगनबाड़ियों के साथ सतत संपर्क पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन में आगनबाड़ी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिलों के प्रवास के दौरान वह पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, सिकल सेल और टी.बी. रोग की समीक्षा अनिर्वायत- करेंगे। उन्होंने अपेक्षा की है कि जिलों में राज्यपाल के प्रवास के दौरान कार्यक्रम स्थल पर टी.बी., सिकल सेल रोग की स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करने की भी जरूरत बताई है।

ट्रम्प बोले-मोदी अच्छे मित्र, ट्रेड बैरियर पर उनसे बात करूंगा

- मोदी बोले- मैं इंतजार कर रहा हूं, बेहतर डील करने के लिए टीमें बात कर रहीं

वॉशिंगटन (एजेंसी)। भारत-अमेरिका ट्रेड डील नेगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही बातचीत जल्द किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचेगी। ट्रम्प ने कहा कि वे सभी तरह के ट्रेड बैरियर खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त, पीएम मोदी से बात के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।ट्रम्प के इस पोस्ट के करीब 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने भी एक एक्स पोस्ट में लिखा, 'भारत और अमेरिका' अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर हैं।

कैबिनेट ने बिहार में दो प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी

- 7616 करोड़ का निवेश होगा, भागलपुर से रामपुरहाट तक रेलवे लाइन भी बनेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। बैठक में 7616 करोड़ रुपए के निवेश वाली बिहार में दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

इसमें बिहार में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के फोर लेन ग्रीनफील्ड मोकामा-मुंगेर सेक्शन के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत बनाई जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 82.400 किलोमीटर और कुल 4447.38 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन (177 किमी) के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल लागत लगभग 3,169 करोड़ रुपए है।

मोकामा-मुंगेर हाईवे मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे शहरों से होकर गुजरेगा और भागलपुर को जोड़ेगा। पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर बेल्ट एक प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है।

यहां पर बंदूक कारखाना और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध कारखाना बनने वाला है। इसके अलावा जमालपुर में लोकोमोटिव वर्कशॉप, मुंगेर में आईटीसी और संबंधित रसद और भंडारण केंद्र हैं।

वहीं, भागलपुर में भागलपुरी सिल्क से जुड़े कारखाने बन रहे हैं। बड़हिया खाद्य पैकेजिंग, प्रसंस्करण और कृषि-गोदाम के लिए एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

टीकमगढ़ परीक्षण संभाग को एम.पी. ट्रांसको की सर्वोत्तम दक्षता ट्रॉफी

भोपाल (एजेंसी)। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के टीकमगढ़ परीक्षण संभाग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए टीकमगढ़ को राज्य स्तरीय सर्वोत्तम दक्षता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जबलपुर मुख्यालय में आयोजित समारोह में एम.पी. ट्रांसको के प्रबंध संचालक श्री सुनील तिवारी ने यह ट्रॉफी टीकमगढ़ टीम को प्रदान की। टीकमगढ़ की ओर से कार्यपालन अभियंता श्री आर.पी. कान्यकुब्ज, सहायक अभियंता श्री जी.पी. राय और श्रीमती चंदा यादव ने यह सम्मान ग्रहण किया। प्रबंध संचालक श्री सुनील तिवारी ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद टीकमगढ़ की टीम की यह उपलब्धि सभी के लिए प्रेरणा है।